भारतीय अर्थव्यवस्था

फ्रैजाइल फाइव से टॉप फाइव

भारत बना
5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

25 करोड़ लोग
गरीबी रेखा से ऊपर आये

भारत बना रहेगा
सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था

डाउनलोड करने के लिए
स्कैन करें

भाजपा प्रकाशन विभाग

श्री जगत प्रकाश नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा

पिछले 10 वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाने के लिए कड़ी मेहनत की है, जबकि उनके शासन में हमारी अर्थव्यवस्था ने विकास के नये कीर्तिमान स्थापित किये हैं। यह बजट विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव भी रखता है। हम 'गरीबी हटाओ' का नारा नहीं देते बल्कि अपनी कड़ी मेहनत एवं नीतिगत पहल से गरीबी मिटाते हैं।

01 फरवरी, 2024

भारतीय अर्थव्यवस्था

फ्रैजाइल फाइव से टॉप फाइव

भाजपा प्रकाशन विभाग
6-ए, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002

प्रकाशकीय

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी एवं सुदृढ़ नेतृत्व में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 2014 में आने से पहले देश का आर्थिक परिदृश्य अत्यंत निराशाजनक था। यह एक स्थापित तथ्य है कि 2004 से 2014 तक कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए के दस सालों के कुशासन ने अपने पीछे बेहिसाब चुनौतियों और न सुलझने वाली समस्याओं, वित्तीय कुप्रबंधन, नीतिगत पंगुता, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और सार्वजनिक धन की लूट की विरासत को छोड़ा था।

जैसाकि हम जानते हैं, श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 8 प्रतिशत से अधिक जीडीपी विकास दर और मजबूत आर्थिक मापदंडों की विरासत को अपने पीछे छोड़ा था। हालांकि, बड़े पैमाने पर राजकोषीय फिजूलखर्ची में लिप्त और प्रमुख सुधारों को पूरा करने में विफल रहने के कारण कांग्रेस नीत यूपीए सरकार के कुछ वर्षों के भीतर यह विरासत तहस-नहस हो गयी। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, गलत प्राथमिकताएं और दूरदर्शिता की कमी ने लोगों के बीच निराशा और अविश्वास का वातावरण पैदा किया। 2014 का भारत गहरे संकट में था, सभी मोर्चों पर भयंकर चुनौतियों का सामना कर रहा था और उच्च मुद्रास्फीति, घटते विदेशी मुद्रा भंडार और विकास की घटती दर के चंगुल में संघर्ष कर रहा था। ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए शासन का काल 'आर्थिक विनाश का दशक' या एक 'खोया हुआ दशक' था।

चुनौतीपूर्ण समय के मध्य 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देश के लिए आशा की किरण बनकर उभरे। लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप श्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने न केवल अर्थव्यवस्था को संकट, निराशा और नीतिगत पंगुता से बाहर निकाला, बल्कि देश के 1.4 अरब लोग के लिए एक गौरवशाली एवं उज्ज्वल भविष्य को सुनिश्चित किया। भारत अब दुनिया की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और यह तीव्रता से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हो चुका है। वर्ष 2014 में 'फ्रैजाइल फाइव' अर्थव्यवस्था से 2024 में वैश्विक विकास में महत्वपूर्ण योगदान के साथ 'टॉप फाइव' में से होना किसी चमत्कार जैसा प्रतीत होता है।

हम इस पुस्तिका के प्रकाशन के लिए सामग्री उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय उद्यमिता, कौशल विकास, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी तथा जल शक्ति राज्य मंत्री **श्री राजीव चन्द्रशेखर** के अत्यंत आभारी हैं। हमें आशा है कि हमारे सुधी पाठकों को यह पुस्तिका उपयोगी लगेगी और वे मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों के दौरान हुए आर्थिक परिवर्तन को गहराई से समझ सकेंगे।

प्रकाशक

भाजपा प्रकाशन विभाग

मार्च, 2024 6-ए, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002

अनुक्रमणिका

प्रकाशकीय

2004-14: एक खोया हुआ दशक 06

'नये भारत' से 'विकसित भारत' तक 08

फ्रैजाइल फाइव से टॉप फाइव के एक दशक का सफर 10

2004-14: एक खोया हुआ दशक

वर्ष 2004 में प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली NDA सरकार ने UPA सरकार को उच्च आर्थिक विकास की संभावनाओं वाली एक स्वस्थ और लचीली अर्थव्यवस्था सौंपी थी। उस समय देश की आथिक विकास दर 8% थी और महंगाई दर औसतन 4% के करीब स्थिर थी, यह पूर्ववती संयुक्त मोर्चा सरकार के कार्यकाल के दौरान रही देश की औसत महंगाई दर 10% से काफी कम थी। NDA के शासन काल के आखिर में देश का चालू खाता अधिशेष में था और वर्ष 1999-2005 के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में 30% की वृद्धि दर्ज की गई थी। NDA सरकार का कार्यकाल सुशासन के माध्यम से राष्ट्र निर्माण का कालखंड था। सरकार ने स्वर्णिम चतुर्भुज, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जैसी महत्वाकांक्षी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लांच किए थे। वहीं, नीतिगत पहलों में सर्व शिक्षा अभियान जैसे परिवर्तनकारी कार्यक्रम तत्कालीन NDA सरकार में ही शुरू किए गए थे। राजकोषीय अनुशासन को संस्थागत बनाया गया था और GST के लिए जमीन तैयार की गई थी। उसी दौरान दूरसंचार क्रांति का सूत्रपात भी हुआ था। भारत को इलीट ग्लोबल न्यूक्लियर क्लब यानी विशिष्ट वैश्विक परमाणु क्लब में शामिल किया गया था। कारगिल युद्ध में भारत की सेना ने विजय प्राप्त करके अपने शौर्य और देश की ताकत का परिचय दिया। साथ ही, देश की अंतरिक्ष के सफर का मार्ग भी प्रशस्त हुआ था। आतंकियों पर लगाम लगाने और आतंकवाद से निपटने के लिए एक कानूनी ढांचा भी बनाया गया था।

मगर, 2004 में UPA की सरकार बनने पर सब कुछ बदल गया। UPA के 10 साल के कार्यकाल दौरान आर्थिक सामाजिक या प्रशासनिक सुधार की जगह आर्थिक कुप्रबंधन और बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार के कारण अवसाद युक्त आर्थिक बदहाली दौर देखने को मिला। UPA सरकार कठिन चुनौतियों और अनसुलझी समस्याओं की एक विरासत अपने पीछे छोड़ गई।

- वर्ष 2014 तक बाह्य आर्थिक भेद्यता का जोखिम बढ़ा, अल्पकालिक

देनदारियों में वृद्धि होने लगी और विदेशी मुद्रा भंडार खाली होने लगा।

- वित्त वर्ष 2008-09 से लेकर 2013-14 के दौरान लगातार छह वर्षों तक राजकोषीय घाटा देश की GDP का करीब 4.5% रहा, जिसके चलते देश में वित्तीय दुर्वस्था का दौर बना रहा।
- महंगाई दर दोहरे अंकों में 10% के करीब रही।
- वर्ष 2001-2011 के दौरान रोजगार वृद्धि दर (1.5%), श्रमबल वृद्धि (2.2-2.3%) के मुकाबले काफी कम थी। NDA सरकार के कार्यकाल के दौरान 1999-2004 में करीब 6 करोड़ नई नौकरियां पैदा हुईं, जबकि UPA के शासन काल में महज 1.5 करोड़।
- UPA के कार्यकाल में वित्तीय अनुशासन में गड़बड़ी, अंधाधुंध कर्ज बांटने और व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार एवं घोटालों का दौर देखा गया। बैंकिंग प्रणाली की निवल परिसंपत्ति के 98% का उपयोग कुछ ही व्यापारिक घरानों के लिए होता था। यही वजह है कि 2005-2014 के दौरान NPA यानी गैर-निष्पादित परिसंपत्ति में सालाना 23% CAGR से बढ़ोतरी दर्ज की गई।

इस तरह 2004 में NDA सरकार से पाई हुई चालू खाता अधिशेष, निम्न महंगाई दर और उच्च आर्थिक विकास दर वाली एक अच्छी अर्थव्यवस्था को UPA सरकार ने एक बदहाल अर्थव्यवस्था में बदल दिया। इससे भारत पर से दुनिया का भरोसा उठ गया और इसकी गिनती दुनिया के 'फाइव फ्रैजाइल' यानी पांच सबसे बदहाल अर्थव्यवस्थाओं में होने लगी, जो पॉलिसी परैलिसिस यानी नीतिगत पंगुता का शिकार बन गयी था।

UPA के 10 साल का शासन काल भारत की आर्थिक तबाही का दशक था - उसे लॉस्ट डिकेड (Lost Decade) के रूप में देखा जा रहा है।

❑❑❑

'नये भारत' से 'विकसित भारत' तक

- हम, भारत के लोग, आज देश के आधुनिक काल के इतिहास के सबसे रोमांचक दौर में हैं।
- हमने 2014 में UPA सरकार को नकार दिया, जो निष्क्रिय शासन-व्यवस्था, वंशवादी राज और तुष्टीकरण की राजनीति का प्रतिनिधित्व करती थी - जिसके चलते भ्रष्टाचार, क्रोनिज्म यानी सत्ता का साथ और लालफीताशाही में फंसकर देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई थी ।
- हमने मजबूत और निर्णायक सरकार (Strong and Decisive Government) बनाने के लिए 2014 में भाजपा को जबरदस्त जनादेश (Strong Mandate) दिया और 2019 में उससे भी ज्यादा जोरदार जनादेश दिया, जिससे वह देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत (Strong Economy) कर सके और सुरक्षित एवं विषम परिस्थितियों से उबरने में समर्थ भारत (Strong and Resilient Bharat) का निर्माण कर सके।
- देश के नागरिकों और सरकार के बीच फिर से विश्वास बहाल कर सके; सबके लिए अवसर पैदा कर सके और देश के युवाओं में दृढ़ संकल्प लेने और अपना सामर्थ्य दिखाने का जोश पैदा कर सके।
- भाजपा सरकार ने 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के बीज मंत्र के साथ भारत को न सिर्फ भ्रष्टाचार-मुक्त बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है और एक उत्तरदायी शासन-व्यवस्था कायम की है, बल्कि 'नया भारत' की मजबूत नींव भी रखी है।
- भारत, जो आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी और सबसे तेजी से विकास करने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बन चुकी है और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है।
- भारत, जो आज देश के करीब 141 करोड़ नागरिकों के जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है ताकि 'कोई पीछे न रह जाए'।

- भारत, जिसने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के नैतिक विचार को अपनाकर 25 करोड़ देशवासियों को बहु-आयामी गरीबी से बाहर निकाला है और आज देश की विकास यात्रा में गरीबों की भी समान भागीदार है।
- भारत, जहाँ नागरिकों की पहचान आज चार जातियों में विभक्त हैं - गरीब, युवा, अन्नदाता और नारीशक्ति ।
- भारत, जहाँ आज युवा शक्ति न सिर्फ सपने देखने का साहस कर रही है, बल्कि— अपने सपनों को साकार भी कर रही है।
- भारत, जिसने सुशासन और राजनीतिक संस्कृति के नये मानक स्थापित किए हैं – ऐसी संस्कृति जो जनसेवा की भावना से ओप्रोत है।
- भारत, जहाँ परिवारवाद और भाई-भतीजावाद के लिए जगह नहीं है। जो सिर्फ विकासवाद का आलिंगन करता है।
- भारत, जो अपने औपनिवेशिक अतीत की बेड़ियों को तोड़ चुका है और अब अन्य हितों की जगह 'राष्ट्रीय हितों' को प्राथमिकता देता है।
- भारत, जहाँ, हर भारतवासी को अपने इस 'नए भारत' पर गर्व है और वे 'विकसित भारत' बनाने के सफर में अपनी भागीदार निभा रहे हैं।
- आज, हमें 'विकास भी विरासत भी' की अपनी विचारधारा पर गर्व है, जहां धर्म संस्कृति और सम्मान हमें प्रेरित करते हैं कि हम कौन हैं और क्या बनना चाहते हैं।
- भाजपा के नेतृत्व में भारत 'अमृत काल' की विकास-यात्रा के अपने मिशन पर अग्रसर है और 2047 में स्वतंत्रता के शताब्दी समारोह मनाने से पहले 'विकसित भारत' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृतसंकल्प है।

भारत का भविष्य है 'विकसित भारत'!

फ्रैजाइल फाइव से टॉप फाइव के एक दशक का सफर

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार को 2014 में एक बुरी तरह तबाह अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी, जिसमें उच्च महंगाई दर, निवेश की कमी और निम्न आर्थिक विकास दर के साथ-साथ विदेशों से आगत पूंजी की स्थिति भी खराब हो गई थी। इस तरह देश की वित्तीय एवं राजकोषीय स्थिति बिगड़ गई थी।

भाजपा सरकार पर चरणबद्ध तरीके से अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने और शासन-व्यवस्था को दुरुस्त करने की बड़ी जिम्मेदारी थी। एक दशक के कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के कारण अर्थव्यवस्था में पड़ी दरारों को भरना था, बेपटरी हुई अर्थव्यवस्था को दुरुस्त एवं इसमें निवेशकों का विश्वास बहाल करना था।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बीते 10 वर्षों के दौरान दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत के साथ काम किया है – पहले देश में बदलाव लाने (Transforming India) और UPA सरकार द्वारा लाई गई तबाही को दुरुस्त करने के लिए और फिर भारत को उच्च प्रदर्शन और उच्च आर्थिक विकास दर के साथ 'नया भारत' (New India) बनाने का मार्ग प्रशस्त किया।

भाजपा सरकार ने आर्थिक और शासन-व्यवस्था के संपूर्ण ढांचे को बदल दिया। कराधान, मुद्रास्फीति प्रबंधन, बैंकिंग, ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस यानी कारोबारी सुगमता, विनिर्माण, फिजिकल और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर सहित हर क्षेत्र में गहन संरचनात्मक सुधार किए गए हैं। इससे भारत की मध्यम एवं दीर्घकालिक संभावना को प्रोत्साहन मिला है।

देश में अपार संभावनाओं और अवसरों के द्वार खुल गए हैं। नई चेतना, नई आकांक्षाओं एवं नए संकल्पों के साथ 'राष्ट्रीय हितों को हासिल करने को लेकर भाजपा सरकार प्रतिबद्ध है। देश में शासन-व्यवस्था की निष्क्रियता को समाप्त करने के लिए सरकार अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन को लेकर ज्यादा प्रतिबद्ध बन गई और 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास,

सबका प्रयास' के मंत्र का पालन करते हुए सभी लोगों और सभी क्षेत्रों के समग्र विकास के साथ एक समृद्ध देश बनाने के अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया है।

इस परिवर्तनकारी दृष्टिकोण के फलस्वरूप 2014 से पूर्व के कालखंड की हर चुनौती से निपटने में कामयाबी मिली है। 2014 के संशय और आशय की जगह अब भरोसे और इरादे ने ली है। पिछले दस साल की प्रगति ने UPA सरकार के पिछले दस वर्षों की रुग्णता और पंगुता को समाप्त कर दिया है। आज़ादी के करीब 67 साल तक भारत और भारतवासियों की क्षमताओं का उपयोग नहीं हो पाया था, लेकिन अब उनके सामने अपनी क्षमताओं का उपयोग करने के अवसर हैं।

भारत की अर्थव्यवस्था जो दस साल पहले तक फ्रैजाइल 5 (Fragile-5) यानी दुनिया की पांच सबसे बदहाल अर्थव्यवस्था में शामिल थी, वह आज दुनिया की पांचवी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है।

- 2014 और 2024 के बीच विदेशी मुद्रा भंडार $315 अरब से दोगुना बढ़कर $617 अरब हो गया। सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार धारण करने के मामले में भारत मौजूदा दौर में चौथे स्थान पर है।
- वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात (Exports of Goods and Services) 2022-23 में बढ़कर अब तक के सार्वकालिक उच्च स्तर करीब $776.4 अरब पर चला गया, जो 2014-15 के $468 अरब की तुलना में 65% से ज्यादा है।
- अर्थव्यवस्था की बाह्य स्थिति को मजबूती मिली है। चालू वित्त वर्ष 2023-24 की पहली छमाही में चालू खाता शेष (current account balance) सुधार के साथ शून्य से महज एक फीसदी कम रह गया है, जबकि एक दशक पूर्व 2012-13 में यह शून्य से 4.8% नीचे था।
- पांच वर्ष 2009-10 से 2013-14 में महंगाई दर जो दोहरे अंकों में थी वह घटकर लगभग आधी रह गई है। पिछले 10 वर्षों के दौरान औसतन महंगाई दर 5.1% रही (कोविड महामारी के दौरान वर्ष 2020 को छोड़कर)।
- देश में लोगों की औसत वास्तविक आय में 50% की वृद्धि हुई है।
- कर संग्रह रिकॉर्ड स्तर पर हो रहा है और सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता

अपने सर्वोत्तम स्थिति में है। राजकोषीय घाटा कोविड वर्ष के दौरान 9.17% तक चला गया था उसमें लगातार गिरावट जारी है और वित्त वर्ष 2024-25 में 5.1% होने का अनुमान है।

- मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान भारत के सेवा क्षेत्र (Service sector) में 97% की वृद्धि दर्ज गई है, जबकि वैश्विक सेवा निर्यात में सिर्फ 36% की वृद्धि हुई है।
- दुनिया की आर्थिक ताकत के तौर पर 2014 में भारत 10वें पायदान पर था, जहां से छलांग लगाते हुए आज दुनिया की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं के समूह में शामिल हो गया है।
- पिछले तीन वर्षों से भारत लगातार 7+% की संवृद्धि दर से विकास कर रहा है। 2014-24 के दौरान (कोविड महामारी वर्ष 2020-21 को छोड़कर) औसत GDP वृद्धि दर 7.1% रही है जबकि 2004-14 के दौरान औसत GDP वृद्धि दर 6.7% थी।

इन उपलब्धियों का श्रेय भाजपा सरकार की समुचित नीतियों, सच्चे इरादों और निर्णायक नेतृत्व से ही संभव हो पाया।

अगर हालिया वैश्विक चुनौतियां सामने नहीं आती तो प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी की सेवा के इस दसवें साल के आखिर में भारत की अर्थव्यवस्था की प्रगति की रफ्तार और भी अधिक होती। वर्ष 2020 के दशक से पूर्व यानी नई सदी के तीसरे दशक की शुरुआत में वैश्विक आर्थिक झटके अपेक्षाकृत दूरस्थ एवं अल्पकालिक थे। हालांकि, 2020 के बाद कोविड महामारी से आरंभ हुई आकस्मिक घटनाओं का दौर लगातार बना हुआ है। मसलन, वैश्विक मुद्रास्फीति में जोरदार वृद्धि और यूरोप में युद्ध के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारी व्यवधान, महंगाई पर लगाम लगाने के लिए दुनियाभर में मौद्रिक नीति में सख्ती का रुख के अलावा मिडिल-ईस्ट और लाल सागर के क्षेत्र की हाल की घटनाओं ने वैश्विक अनिश्चितताओं को और बढ़ा दिया है।

बाकी दुनिया की तरह भारत भी इन घटनाओं से अछूता नहीं है।

लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सभी प्रमुख उन्नत व विकसित अर्थव्यवस्थाएं बेपटरी हो गई हैं और उनको पटरी पर लाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है जबकि भारत विकास पथ पर है और तेज़ी से बढ़ रहा है।

सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत का प्रदर्शन बेहतर है और वैश्विक स्तर पर रिकवरी के मामले में अग्रणी बना हुआ है। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था है। भारत की सालाना आर्थिक विकास दर मार्च 2025 के आखिर तक लगातार चार वर्षों के दौरान 7% या उससे अधिक रहने की संभावना है। जाहिर है कि उच्च विकास दर रहने से देश में नई नौकरियां पैदा होंगी और देशवासियों का जीवन-स्तर बेहतर होगा।

आज पूरी दुनिया देख रही है कि भाजपा सरकार किस गति और कुशलता से काम करती है और हमारे लक्ष्यों की अहमियत और हमारे संकल्प की ताकत क्या है। भारत की संभावनाओं पर भरोसा अब तक के उच्चतम स्तर पर है। घरेलू और विदेशी दोनों निवेशक भारत की आर्थिक विकास की संभावनाओं को लेकर काफी आशावान हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ आकर्षक अवसरों की उम्मीद करते हैं। भारत का अब हर किसी के पोर्टफोलियो में होना अनिवार्य बन गया है।

दुनिया कह रही है कि यह भारत का समय है!

भारत मौजूदा दौर में दुनिया की सबसे तेजी से विकास करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत दुनिया के 'फ्रैजाइल-5 से चलकर 'टॉप-5' अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह बना चुका है। भारत अब $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की ओर उन्मुख है। भारत का अगला लक्ष्य 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल करना और 2047 से पहले 'विकसित भारत' का लक्ष्य हासिल करना है।

संक्षेप में कहें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में BJP सरकार ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान कांग्रेस नीत UPA सरकार के शासन के दौरान बने गड्ढों को देश में बदलाव लाकर भर दिया 'Transforming India'। उसके बाद दूसरे कार्यकाल में 'नये भारत' की नींव रखकर उसके निर्माण को कार्यरूप दिया। सरकार अब 'विकसित भारत' के हमारे सामूहिक मिशन के लिए विकास को गति देगी। विकसित भारत के इस सफर में सरकार वर्तमान और अमृत काल में अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान देश के विकास की आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम होगी।

भाजपा सरकार "विकसित भारत" के निर्माण की अपनी प्रतिबद्धता के प्रति पूरी तरह समर्पित है। इस सरकार का प्रत्येक कार्य और प्रत्येक विचार इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समर्पित है।

II. जन कल्याण, गरीब कल्याण–'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास'

2004-14 का काल UPA का लॉस्ट डिकेड (Lost decade) पूरे न किए गए वादों और भाई-भतीजावाद का काल था, जहां जनता का जीवन कष्टपूर्ण बना रहा - सत्ता के साथी यानी क्रोनी मालामाल हो गए, जबकि गरीब सरकारी नीतियों और योजनाओं की पहुंच से बाहर, गरीब ही बने रहे। लीकेज (Leakage) और भ्रष्टाचार इस कदर व्याप्त था कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने खुद कहा था कि गरीबों के लिए भेजे जाने वाले प्रत्येक 1 रुपये में से सिर्फ 15 पैसा ही गरीबों तक पहुंचता है। आज़ादी के 65 साल बाद भी देश की अधिकांश आबादी बैंक और नल से पेयजल की उपलब्धता, रसोई, शौचालय, स्वास्थ्य सेवाएं और बीमा जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित रही। **'गरीबी हटाओं'** के नारे से गरीबी नहीं मिटी, लेकिन गरीबी की रेखा जरूर बन गई। ना वास्तविक परिवर्तन आया, ना सुधार।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि हर व्यक्ति तक विकास लाभ पहुंचाए बिना आर्थिक विकास अधूरा है। पंडित श्री दीनदयाल उपाध्याय जी ने 'अंत्योदय' की अपनी अवधारणा में इस बात का प्रतिपादन किया है। तदनुसार, पिछले दस वर्षों में भाजपा सरकार सभी के लिए सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास के दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है।

सरकार ने 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के बीज मंत्र के साथ लक्षित हस्तक्षेपों और सरकारी योजनाओं और बुनियादी सुविधाओं की परिपूर्णता (saturation) पर ध्यान केंद्रित किया है, जिससे आम आदमी पिछले 65 वर्षों से वंचित था।

2014 में जब भाजपा की सरकार बनी थी, तब ग्रामीण स्वच्छता कवरेज सिर्फ 39% था और 16% से अधिक घरों में बिजली नहीं पहुंच पायी थी। गांवों में बिजली की उपलब्धता औसतन रोजना 12 घंटे से भी कम थी। वहीं, 45% घरों में खाना पकाने के लिए रसोई गैस नहीं थी। अगस्त 2019 तक, सिर्फ 16.8% परिवारों को नल से पानी के कनेक्शन मिल पाए थे।

सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन (SBM), जल जीवन मिशन (JJM),

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (Saubhagya), प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY), प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY), प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) और कई अन्य लक्षित हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित किया है। इन योजनाओं और पहलों ने आजादी के बाद दशकों तक सहन की गई असहायता की स्थिति के बजाय सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता के माध्यम से नागरिकों, विशेषकर महिलाओं के जीवन स्तर और आत्म-सम्मान को बढ़ाया है।

- सरकार ने कार्यक्रमों के कार्यान्वयन एवं डिलीवरी के मामले में पूर्ववर्ती सरकार के मुकाबले बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड पेश किया है और विकास का लाभ व्यापक स्तर पर लोगों को मिल रहा है।
- नई एकीकृत खाद्य सब्सिडी योजना 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' के तहत लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया जा रहा है। सरकार ने इस योजना को पांच साल के लिए बढ़ा दिया है - यह योजना 2028 के आखिर तक जारी रहेगी। कोविड के दौरान और बाद में लगभग 28 महीनों तक सरकार ने इन लाभार्थियों को 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति मुफ्त अतिरिक्त खाद्यान्न भी वितरित किया है ।
- केंद्रीय भंडार, NAFED और NCCF की स्थायी और मोबाइल आउटलेट से भारत आटा 27.5 रुपये प्रति किलो और भारत दाल 60 प्रति किलो के पैकेट और 55 प्रति किलो (30 किलो पैकेट) किफायती दारों पर बेची जा रही है।
- सरकार ने 'पीएम आवास योजना' के तहत पिछले 10 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों 2.56 करोड़ से अधिक परिवारों को और शहरी क्षेत्र में 80 लाख परिवारों को मकान प्रदान किए हैं। विशेष रूप से, ग्रामीण भारत में 70% घर महिलाओं के नाम रजिस्टर्ड हैं।
- अब बिजली की सार्वभौमिक पहुंच है, घरेलू विद्युतीकरण बढ़कर 99.99% हो गया है। ग्रामीण भारत में औसत दैनिक बिजली उपलब्धता भी प्रति दिन 21 घंटे और शहरी भारत में 23.8 घंटे से अधिक हो गई है।
- लगभग 1 करोड़ नागरिकों को अब प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत

रूफटॉप सोलर मिलेगा, जो उनके बिजली के बिलों को कम करेगा और भविष्य में बचत का रास्ता खोलेगा ।

- भारत ने सफाई और स्वच्छता के मोर्चे पर बड़े पैमाने पर प्रगति की है। जहां UPA सरकार ने 2011-2014 में केवल 1.8 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया था, वहीं मोदी सरकार ने 2014-2024 तक 11.5 करोड़ घरेलू शौचालयों का निर्माण किया, जो उल्लेखनीय प्रगति का सूचक है। भारत को 'ओपन डिफेक्शन फ्री' यानी खुले में शौच से मुक्त बनाने में 100% सफलता हासिल मिल चुकी है।
- ग्रामीण क्षेत्र में पाइप से जलापूर्ति वाले घरों का कुल कवरेज बढ़कर लगभग 74.2% हो गया है। जल जीवन मिशन लांच होने के बाद देश में 11.03 करोड़ यानी 69% से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को पाइप से पानी की आपूर्ति का कनेक्शन मिला है।
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ परिवारों को किफायती दरों पर रसोई गैस प्रदान की गयी है, जिससे स्वच्छ ईंधन तक लोगों की सार्वभौमिक पहुंच बढ़ाने में सफलता हासिल हुई है।
- सरकार ने सभी लाभार्थियों के लिए 14.2 kg सिलेंडर की कीमत में 200 की कमी की है। यह कटौती प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 12 सिलेंडरों तक के लिए प्रदान की जाने वाली 300 प्रति सिलेंडर की बढ़ी हुई लक्षित सब्सिडी के अतिरिक्त है।
- प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 51.7 करोड़ से अधिक न्यूनतम शून्य-बैलेंस वाले बैंक खाते खोले गए हैं। इस योजना ने विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार से DBT प्राप्त करने के लिए नागरिकों के वित्तीय कवरेज को सक्षम बनाया है।
- सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना – 'आयुष्मान भारत - पीएम जन आरोग्य योजना' भी शुरू की है। इस योजना के तहत वर्तमान में 30 करोड़ से अधिक परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवरेज मिल रही है।
- प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना से चिकित्सा पर होने वाले खर्च को लेकर नागरिकों की चिंताओं को दूर हुई है। दवाओं के दाम में कमी आने

से नागरिकों को 28,000 रुपये करोड़ से अधिक की बचत हुई है। करीब 2,000+ दवाएं और सर्जिकल डिवासेस 50% सस्ते हो गए हैं। UPA शासन काल के दौरान सिर्फ 164 जनौषधि स्टोर (और 87 चालू थे) थे। वहीं, भाजपा सरकार ने 2014-2023 के दौरान 10,000 जन औषधि स्टोर खोलकर एक रिकॉर्ड कायम किया है।

भाजपा सरकार ने सबको सशक्त बनाया

देश में चार प्रमुख जातियों— 'गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता' की भलाई और तरक्की को लेकर सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उपर्युक्त अनेक पहलों का समाज के विभिन्न वर्गों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है, जिससे वे हमारे आर्थिक विकास में असली योगदानकर्ता बन गए हैं।

देश के खासतौर से ग्रामीण एवं अति पिछड़े क्षेत्रों के 25 करोड़ से अधिक लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं और उनके जीवन की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। यह सरकार के 'अंत्योदय' के दर्शन को दर्शाता है।

सरकार की पहलों से विशेष रूप से महिलाओं को रोजमर्रा की जिंदगी कठिनाइयों से मुक्ति है। चूल्हे के धुएं से होने वाली सांस संबंधी गंभीर बीमारियों से महिलाओं की रक्षा हुई है। जलावन की लकड़ी इकट्ठा करने या पानी के लिए लंबी दूरी तय करने जैसी दैनिक कठिनाइयां भी दूर हुई हैं। शौचालय की सुविधा होने से महिलाओं के सम्मान कर रक्षा हुई है। खुले में शौच के लिए जाने को लेकर उनके मन में हमेशा जो असुरक्षा एवं भय का भाव बना रहता था वह अब दूर हो गया है। देशभर में 9 करोड़ से अधिक महिलाओं को 90.5 लाख स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया गया है, जिनमें से 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं और अन्य 2 करोड़ को आगे लक्षित किया गया है। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत 15,000 ड्रोन प्रदान किये जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा महिलाएं अब शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। 10 वर्षों में उच्च शिक्षा में नामांकन की दर 28% बढ़ी है। सरकार ने हर क्षेत्र में भारतीय महिलाओं को समर्थन देकर उन्हें प्रोत्साहित किया है। आज चाहे वह चिकित्सा हो, खेल या फिर रक्षा, सभी क्षेत्रों में महिलाएं उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं और देशसेवा में अपना योगदान दे रही हैं।

सरकार ने समय-समय पर अन्नदाता की उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी करके इसे अभूतपूर्व स्तर पर ला दिया है। साथ ही, कृषि उपज की सरकारी खरीद भी अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के तहत 11 करोड़ से अधिक अन्नदाताओं को 2.8 लाख करोड़ रुपये की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। किसानों को उनके राज्यों के बाहर उपज बेचने में सक्षम बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) नामक एक डिजिटल इको-सिस्टम बनाया गया है, जिसमें 1,389 से अधिक मंडियों को एकीकृत किया गया है और 1.8 करोड़ से अधिक किसान वर्तमान में इसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आधुनिक प्रसंस्करण और कृषि-अपशिष्ट को कम करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के माध्यम से आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है, जिससे खेत से लेकर खुदरा आउटलेट तक आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन किया गया है, जिससे 38 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं।

सरकार प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN) के द्वारा 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों के माध्यम से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों तक भी पहुंच रही है जो विकास के दायरे से बाहर रहे हैं। इसमें बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, बिजली, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी और स्थायी आजीविका के अवसरों तक बेहतर पहुंच शामिल हैं।

आकांक्षी जिले और खंड कार्यक्रम जैसी महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से सरकार ने आर्थिक अवसरों के सृजन सहित जिलों और ब्लॉकों के तेजी से विकास में राज्यों की सहायता की है। इसने पहले ही देश के 112 जिलों में 25 करोड़ से अधिक लोगों के जीवन को बदल दिया है और अब चिह्नित किए गए 500 ब्लॉकों में लोगों के जीवन की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

मोदी सरकार द्वारा निर्धारित 'विकसित भारत' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश में पहली बार 'संकल्प यात्रा' निकाली गई है, जिसमें सरकार घर घर जाकर ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर योजना में तेजी से पूर्ण कवरेज लागू हो और कोई पात्र लाभार्थी वंचित न रह जाए। अब तक, 19 करोड़ से

अधिक नागरिक यात्रा में भाग ले चुके हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार द्वारा शासन-व्यवस्था में व्यापक बदलाव लाया गया है- सरकार और देश सभी नागरिकों के बीच विश्वास बहाल हुआ है। सरकार ने दिखा दिया है कि सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि यह भाजपा और नरेंद्र मोदी की गारंटी है।

III. सिटिज़न फर्स्ट (Citizen-First) एप्रोच और 'पारदर्शी शासन-व्यवस्था' से जनता के जीवन में बदलाव

दशकों तक भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखा जाता रहा जहां काफी संभावनाएं हैं, लेकिन खराब और भ्रष्ट शासन प्रणाली के कारण भारत गरीबी से उबर नहीं पाया। 2004-14 का युग भ्रष्टाचार और घोटालों के युग के रूप में सामने आया है, जिसके दौरान हुए भ्रष्टाचार और घोटालों के बड़े-बड़े मामलों ने देश को हिलाकर रख दिया। योग्यता और नागरिक कल्याण को ताक पर रखकर वंशवाद की राजनीति ने भाई-भतीजावाद को प्रोत्साहित किया। सभी सरकारी गतिविधियों में व्यापक भ्रष्टाचार था, जिसमें खरीद, प्राकृतिक संसाधनों का आबंटन, और नियामक अनुमोदन, कर संग्रह आदि शामिल थे। व्यवस्था में बड़े पैमाने पर लीकेज (Leakage) थे और आम आदमी को बिचौलियों की दया पर छोड़ दिया गया था। घोटालों और भ्रष्टाचार के मामलों ने लोगों के विश्वास को हिला दिया था और सार्वजनिक पद के दुरुपयोग पर देश की जनता के बीच बड़ी नाराजगी थी । वास्तव में UPA सरकार **'भ्रष्टाचार की गारंटी'** थी!

वर्ष 2014 में, भाजपा सरकार ने 'सिटिज़न फर्स्ट' (Citizen-First) और 'मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सीमम गवर्नेंस' 'Minimum Government, Maximum Governance' दृष्टिकोण के साथ एक पारदर्शी, जवाबदेह, जन-केंद्रित और त्वरित विश्वास-आधारित प्रशासन प्रदान करके 'भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की गारंटी' दी।

भाजपा सरकार ने भारत के कमज़ोर भ्रष्ट शासन के बारे में पुराने आख्यान को पूरी तरह से बदलने के लिए प्रौद्योगिकी और जैम ट्रिनिटी (JAM Trinity) का इस्तेमाल किया और शासन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, जिससे UPA/कांग्रेस युग में आने वाली निष्पादन संबंधी चुनौतियों का

समाधान हुआ।

डिजिटल इंडिया को भारतीय नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण में तेजी लाने के लिए लॉन्च किया गया था। इसके द्वारा ऑनलाइन, पेपरलेस, फेसलेस, पारदर्शी और कैशलेस के रूप में शासन-व्यवस्था के दृष्टिकोण को फिर से परिभाषित करके डिजिटल क्रांति को जमीनी स्तर पर लाया गया है ।

सरकार ने जैम ट्रिनिटी (JAM Trinity)– जन धन, आधार और मोबाइल को लागू और मजबूत किया और 'डीबीटी (DBT)' जो पहले 'डीलर ब्रोकर ट्रांसफर (Dealer Broker Transfer)' के रूप में जो बदनाम था, वह अब सही सही अर्थ में 'प्रत्यक्ष लाभ ट्रांसफर (Direct Benefit Transfer)' में बदल गया – जिससे सिस्टम में लीकेज को रोकना, बिचौलियों को हटाना और सार्वजनिक धन का प्रत्येक रुपया अब लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचना, (अतीत में जहां केवल 15 पैसे प्रति रुपये ही लाभार्थियों तक पहुंचा करता था) आदि सुनिश्चित हो सका। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भारत के DBT को ऐसे ही नहीं एक 'लॉजिस्टिक चमत्कार' कहा है।

यह अंतिम मील तक पहुंचने की सरकार की प्रतिबद्धता ही है, जिसने अब तक DBT के माध्यम से 34 लाख करोड़ से अधिक के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की है। इस प्रक्रिया में करीब 10 करोड़ फर्जी लाभार्थियों को सिस्टम से बाहर निकाला जा चुका है, जिससे 2.73 लाख करोड़ रुपये से अधिक के सार्वजनिक धन को गलत हाथों में जाने से बचा है। मिसाल के तौर पर LPG सब्सिडी के लिए DBT का उपयोग करने वाली जैम-पहल योजना से लीकेज में करीब 24% की कमी आई है।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत अपने नागरिकों के जीवन को बदलने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में, दुनिया का प्रमुख देश बन गया है, जिससे शासन और लोकतंत्र में सुधार और शासन में नागरिकों के विश्वास में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। पिछले 10 वर्षों में इसने आधार, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI), डिजिलॉकर, UMANG, MyGov इत्यादि समेत अनेक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) बनाए गए हैं; जिसने नागरिकों के

जीवन की सुगमता के अनुभव बढ़ा है, पारदर्शिता और जवाबदेही पैदा हुई है और दिन-प्रतिदिन के जीवन से भ्रष्टाचार का खात्मा हुआ है।

सरकार ने सबसे कम दरों के साथ 4G के तहत आबादी का व्यापक कवरेज और 2023 में दुनिया का सबसे तेज़ 5G रोलआउट सुनिश्चित किया है। लगभग 6.78 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल और कम लागत वाले डेटा (औसतन 1 जीबी के लिए 10.1 रुपये) ने भारत में इंटरनेट और मोबाइल क्रांति की शुरुआत की है। अब किसान मौसम के अपडेट की जांच, बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा भुगतान की जानकारी, छात्रों को छात्रवृत्ति की जानकारी, डॉक्टर द्वारा टेली-मेडिसिन का परामर्श, मछुआरे द्वारा फिशिंग ग्राउंड्स की जांच और छोटे कारोबारियों को ऋण, सब अपने फोन पर बस एक टैप के साथ मिलता है!

आज, दुनिया के कुल रीयल-टाइम (real-time) डिजिटल लेनदेन का 46% लेनदेन भारत में होता है। केवल 2023 में UPI के माध्यम से रिकॉर्ड 11 हजार करोड़ से अधिक लेनदेन किए गए, एक ऐसी सुविधा जो अब दुनिया के अन्य देशों में भी उपलब्ध है।

यह केवल डिजिटल इंडिया के कारण है, कि सरकार दुनिया के सबसे बड़े मुफ्त भोजन कार्यक्रम को लागू कर सकी है और कोविड-19 संकट के दौरान समाज के कमजोर वर्गों को अन्य प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण कर सकी है।

सरकार ने एक पारदर्शी, कुशल और समावेशी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) की शुरुआत करके सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में क्रांति ला दी। इसने 11,897 से अधिक उत्पाद श्रेणियों और 321 से अधिक सेवा श्रेणियों के लिए एक बाजार (marketplace) बनाया है, जिसमें 7 लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के ऑर्डर का आदान-प्रदान हो चुका है, और जिससे 65,000 करोड़ रुपये से अधिक की बचत की हुई है।

आज, DPI 21वीं सदी में एक नया 'उत्पादन कारक' बन गया है, जिसका उपयोग जीवन के हर क्षेत्र में किया जा रहा है और भारत की क्षमताओं को बढ़ावा मिल रहा है। ये अधिक औपचारिकता, उच्च वित्तीय समावेशन, बाजारों तक बेहतर पहुंच, कम लेनदेन लागत के कारण दक्षता लाभ पैदा करने में सहायक रहे हैं, जो अंततः त्वरित आर्थिक विकास में तब्दील हो रहे

हैं।

भारत आज दुनिया में अग्रणी डिजिटल इकॉनमी है और सरकार नए युग के डिजिटल बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित कर रही है जिसमें 5G/6G तकनीक, चिप निर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्वांटम कंप्यूटिंग आदि शामिल हैं। दुनिया का मानना है कि अगर किसी देश में AI का सबसे ज्यादा उपयोग करने की क्षमता है, तो वह भारत है। डिजिटल इंडिया अभियान देश के युवाओं और विभिन्न पेशेवरों के लिए रोजगार के कई अवसर भी लाएगा।

यह वास्तव में भारत का टेकेड (Techade) है - प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीयों के द्वारा और भारतीयों के लिए अवसरों से भरा दशक।

IV. भारतीय वित्तीय क्षेत्र: परेशानी से परफॉरमेंस तक

प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में सरकार बनाते ही इस विषय को संज्ञान में लिया कि 'विकसित भारत' बनाने के लिए एक अत्यंत पारदर्शी, कुशल एवं व्यापक वित्तीय प्रणाली की आवश्यकता है।

2014 में भारतीय बैंकिंग प्रणाली गंभीर संरचनात्मक समस्याओं से जूझ रही थी। यह UPA सरकार से मिली एक अति निंदनीय विरासत थी। UPA सरकार में शामिल राजनेताओं के दबाव में अयोग्य कारोबारियों को कर्ज दिए गए, जिसके चलते नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA) बढ़ते चले गए और देश की समग्र ऋण वितरण दर में गिरावट आई।

मोदी सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से लिया और पूर्ववर्ती सरकार द्वारा फैलाई इस गंदगी की सफाई के लिए व्यापक रणनीति बनाई। इस समस्या के मूल कारण से निपटने के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए, जिनमें बैंकों का एकीकरण, 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करके बैंकों का अभूतपूर्व पुनर्पूंजीकरण और Insolvency and Bankruptcy Code 2016 का कार्यान्वयन आदि करना शामिल हैं।

इसके फलस्वरूप बैंकिंग सेक्टर में सराहनीय सुधार हुआ और इससे संपूर्ण वित्तीय क्षेत्र की सेहत सुधरी है। सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में सकल NPA (gross NPAs as a percentage of gross advances) सितंबर 2023 में दशक के सबसे निचले स्तर 3.2% पर आ गया है, जोकि

2017-18 में सर्वाधिक स्तर 11.2% पर आ गया था। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की लाभप्रदता की बहाली, राहत, पुनर्प्राप्ति और कायाकल्प की अपनी कहानी बताती है।

निर्णायक नेतृत्व, मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और सरकार की दूरदर्शी नीतियों के कारण है कि वित्तीय क्षेत्र आखिरकार आर्थिक विकास का बाधक नहीं बल्कि समर्थक बन गया है- जोकि 'विकसित भारत' के लिए अत्यंत आवश्यक है!

V. सार्वजनिक वित्त: खराब स्थिति से उबरकर मजबूती दौर

2014 में मोदी सरकार के सामने एक और बड़ी समस्या सार्वजनिक वित्त की खराब स्थिति और राजकोषीय खर्च के विकल्पों की सीमित गुंजाइश (limited fiscal space) थी अर्थात खर्च के विकल्पों में लचीलापन था। कर प्रणालियाँ आम नागरिक की समझ के बाहर थी और पारदर्शिता की कमी के कारण ईमानदार करदाता और व्यापारी दोनों ही परेशान थे।

परन्तु पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने भारत की राजकोषीय प्रणाली को एक सुव्यवस्थित 'कर एवं व्यय तंत्र' के रूप में बदलने के लिए अथक प्रयास किए हैं।

सरकार ने ऐतिहासिक वस्तु एवं सेवा कर (GST) को लागू करके देश को एक आधुनिक कर प्रणाली प्रदान की है। इसने कर दरों को कम करने और तर्कसंगत बनाने के साथ-साथ सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 400 से अधिक दरों और कमीशन को समाप्त कर दिया है। वर्तमान में प्रभावी औसत GST दर लगभग 11% है, जो वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमानित 17% की राजस्व तटस्थ दर से काफी कम है।

भारत ने व्यक्तिगत कराधान प्रणाली में भी सुधार किया है, जिसमें 7 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को नई कर व्यवस्था में आयकर का भुगतान करने से छूट दी गई है, जोकि वित्त वर्ष 2013-14 में सिर्फ 2.2 लाख रुपये तक की वार्षिक आय तक थी।

सरकार ने देश में फेसलेस टैक्स असेसमेंट (Faceless tax assessment) प्रणाली भी शुरू किया है।

इन सभी सुधारों के परिणामस्वरूप देश में अब रिकॉर्ड कर संग्रह हो रहा

है जो एक बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत आवश्यक है।

- सकल कर राजस्व 2013-14 में 11.4 लाख करोड़ से 2023-24 में लगभग तिगुना होकर 33.6 लाख करोड़ रुपये हो गया है; इसी अवधि के दौरान प्रत्यक्ष कर संग्रह भी तीन गुना बढ़कर 19.45 लाख करोड़ रुपये हो गया है।
- यूपीआई (UPI), क्रेडिट और डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग जैसे ऑनलाइन तंत्र के माध्यम से करों के भुगतान में आसानी हुई है। न केवल टैक्स संग्रह की लागत कम हो गई है, बल्कि टैक्स रिटर्न का कुल औसत प्रसंस्करण समय (Processing time) 2013-14 में 93 दिनों से घटकर मात्र 10 दिन हो गया है, जिससे रिफंड तेजी से हो रहा है।
- 2014 के बाद से नागरिकों द्वारा कर बचत के रूप में लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये बचाए गए हैं!
- पिछले 5 वर्षों में GST संग्रह UPA के 10 वर्षों के दौरान पूरे अप्रत्यक्ष कर संग्रह से अधिक रहा है। GST से मासिक औसत राजस्व 2017-18 में 90,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 1.7 लाख करोड़ रुपये हो गया है।
- GST ने दिसंबर, 2017 से मार्च, 2023 तक परिवारों को प्रति माह लगभग 45,000 करोड़ बचाने में मदद की है।

सरकार ने आखिरकार अत्यंत आवश्यक सुविधानुसार राजकोषीय व्यय की गुंजाइश (fiscal space) प्राप्त कर ली है। करदाताओं से एकत्र कर राजस्व को सभी भारतीयों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उपयोग किया जा रहा है। सरकार ने स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, जल, आवास, बुनियादी ढांचे, रक्षा आदि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सार्वजनिक खर्च बढ़ाया है, जिससे आम नागरिकों के जीवन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और भारत की आर्थिक वृद्धि को और अधिक बढ़ावा मिला है।

कर सुधारों और कम कर दरों के कारण बेहतर अनुपालन हुआ है, जिससे भारत में कर आधार (Tax Base) का विस्तार हुआ है। 2022-23 में प्रत्यक्ष कर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या दोगुनी से अधिक होकर 7.78 करोड़ हो गई; और अप्रैल 2023 में सक्रिय GST करदाताओं की

संख्या बढ़कर 1.4 करोड़ हो गई। कर आधार में वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि लोगों को सरकार पर भरोसा है और उनका मानना है कि भुगतान किया गया कर जनता की भलाई के लिए खर्च किया जा रहा है।

VI. अभूतपूर्व गति और पैमाने पर विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचों का निर्माण

UPA सरकार बुनियादी ढांचों के मामले में विफल रही, जबकि हमारे आसपास के देश आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहे हों, लेकिन UPA के दोनों कार्यकाल में सरकार ने कभी इसपर ध्यान नहीं दिया और न ही इसके लिए संसाधनों का उपयोग किया। UPA के खोए हुए दशक (Lost Decade) के दौरान पिछली NDA सरकार द्वारा शुरू की गई तमाम बुनियादी ढांचों की परियोजनाओं की रफ्तार ठप पड़ गई, चाहे वह स्वर्णिम चतुर्भुज हो, ग्राम सड़क योजना हो या उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम गलियारे हों। निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में कई बड़ी और महत्वाकांक्षी बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ या तो "निर्माणाधीन" स्थिति में थीं या उनपर रोक लगा दी गई थी। अन्य कुछ खराब योजनाएं, संचालन और प्रशासनिक वजहों से लंबित पड़ी थी। बुनियादी ढांचों के निर्माण और लॉजिस्टिक बाधाओं की चुनौतियों की जानबूझकर उपेक्षा करने के कारण औद्योगिक और आर्थिक विकास ठप पड़ गया।

<u>भाजपा सरकार ने अभूतपूर्व स्तर के फोकस, गति और पैमाने सहित एक भव्य रणनीति के साथ बुनियादी ढांचे की की पुनर्कल्पना की।</u>

- बड़ी संख्या में ठप पड़ी व लंबित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की रफ़्तार तेज की गयी और उन्हें पूरा किया गया, जैसे कि सरयू नहर (43 वर्षों के बाद पूरा हुआ), बोगीबील ब्रिज (16 वर्षों के बाद), कोसी महासेतु (86 वर्षों के बाद), जेवर हवाई अड्डा (16 वर्षों के बाद), बीदर कलबुर्गी रेल लाइन (17 वर्षों के बाद) आदि।
- पिछले 10 वर्षों में सरकार ने रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय किया, जो 2004-14 के दौरान केवल 12 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2014-24 के दौरान 44 लाख करोड़ रुपये हो गया, सिर्फ 2024-25 के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपये का बजट रखा गया है!
- राष्ट्रीय राजमार्गों (NH) की लंबाई 90 हजार km से बढ़कर 1 लाख 46 हजार किलोमीटर हो गई है और चार लेन वाले NH की लंबाई 2.5

गुना बढ़ गई है। आज, राजमार्ग 28 km/दिन (वित्त वर्ष 2014-15 में 12km/दिन की तुलना में) की गति से बनाए जा रहे हैं।

- 25 हजार किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनें बिछाई गई हैं, जो कई विकसित देशों में रेलवे लाइनों की कुल लंबाई से भी अधिक है। 2022-23 में हर दिन 14km से ज्यादा रेल पटरियां बिछाई गईं; इस वर्ष का लक्ष्य 16 km/प्रतिदिन प्राप्त करना है।
- पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत अब 39 रूटों पर चल रही है। भारत को पहली नमो भारत ट्रेन और पहली अमृत भारत ट्रेन भी मिली।
- विद्युतीकृत रेल मार्ग दोगुने से भी अधिक हो गए हैं और भारत रेलवे के 100% विद्युतीकरण के करीब है।
- प्रमुख बंदरगाहों पर कार्गो प्रबंधन क्षमता दोगुनी हो गई है और प्रमुख बंदरगाहों पर कार्गो यातायात 581 मीट्रिक टन से बढ़कर 784 मीट्रिक टन हो गया है।
- परिचालन हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से दोगुनी होकर अब 149 हो गई है। 'उड़े देश का आम नागरिक (UDAN) योजना' के तहत दूरदराज और कम सेवा वाले क्षेत्रों को कवर करने वाले 517 नए मार्गों का पर विमान सेवा का परिचालन हो गया गया है, इन मार्गों पर परिचालित UDAN सेवा का आनंद 1.3 करोड़ से अधिक लोग उठा चुके हैं ।
- हवाई यात्रा की मांग में वृद्धि के बाद भारतीय वाहकों ने सक्रिय रूप से 1000 से अधिक नए विमानों के ऑर्डर दिए हैं। विमान रखरखाव की आवश्यकता से आगे चलकर प्रशिक्षित इंजीनियरों और अन्य व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
- गांवों में लगभग 3.75 लाख km नई सड़कें बनाई गई हैं - देश की लगभग सभी पात्र बस्तियों को हर मौसम के अनुकूल सड़कों से जोड़ा जा चुका है ।
- UPA सरकार में कमजोर बुनियादी ढांचे वाले भारत की तुलना में देश ने कई विश्व रिकॉर्ड तोड़े हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल - चिनाब पुल, 10,000 फीट से अधिक ऊंची दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग - अटल सुरंग, भारत का सबसे बड़ा समुद्री पुल - अटल सेतु - सभी BJP

सरकार में बनाए गए हैं।

- सरकार ने कोयला क्षेत्र को प्रभावी ढंग से पारदर्शी बना दिया है और वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी (One Nation One Grid One Frequency) ने ऊर्जा आवश्यकता और ऊर्जा आपूर्ति के बीच के अंतर को 2013-14 के 4.2% से घटाकर 2023-24 में केवल 0.3% कर दिया है ।

इससे मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी में सुधार हो रहा है, लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार हो रहा है, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का अंतराल समाप्त हो रहा है, व्यवधान कम हो रहे हैं और परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित हो रहा है। इससे विनिर्माण और निर्यात में वैश्विक स्तर भारत की प्रतिस्पर्धा बढ़ी है।

सरकार एक कदम और आगे बढ़ते हुए अब PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (PM Gati Shakti National Master Plan) और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (National Logistics Policy) के तहत 'संपूर्ण सरकार' और सहकारी संघवाद के दृष्टिकोण के माध्यम से बुनियादी ढांचे की एकीकृत और समग्र योजना एवं कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे रही है। मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार हो रहा है। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की कमी को दूर कर, रुकावटों को कम किया जा रहा है एवं परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित किया जा रहा है। इससे विनिर्माण और निर्यात में वैश्विक स्तर भारत की प्रतिस्पर्धा बढ़ी है।

'राष्ट्र प्रथम' के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता ने भारत के बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र के मानक को ऊंचा कर दिया है जो एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में कार्य कर, देश को निवेश आकर्षित करने और वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में इसकी भागीदारी को व्यापक बनाने में सक्षम कर रहा है।

<u>बुनियादी ढांचा अब गैर-प्रदर्शन का बहाना नहीं है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के बेहतर प्रदर्शन का सूत्र है।</u>

VII. आत्मनिर्भरता – डिजिटलीकरण, नवाचार और विनिर्माण को प्रोत्साहन

दुनियाभर में निवेशक जब ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस यानी कारोबारी सुगमता की तलाश में थे तब UPA सरकार ने नीतिगत अनिश्चितता और शत्रुता का वातावरण पैदा किया। UPA

सरकार के दौरान निराशाजनक निवेश के माहौल के कारण अत्यंत साहसी निवेशकों को भी विदेशों में अवसर तलाशने के लिए मजबूर होना पड़ा।

भाजपा सरकार ने 2014 के निचले स्तर, जब नोकिया जैसी वैश्विक बड़ी कंपनियों को खदेड़ दिया गया था, तब से लेकर वैश्विक और भारतीय बड़ी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित करने तक निवेशकों का विश्वास बहाल करने का बड़ा काम अपने ऊपर लिया। प्रधानमंत्री ने 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' का स्पष्ट आह्वान किया - ताकि दुनियाभर के संभावित निवेशकों और भागीदारों को 'न्यू इंडिया' के विकास की कहानी में भाग लेने के लिए खुला निमंत्रण दिया जा सके!

सरकार ने 41,000 से अधिक अनुपालनों को हटाकर या सरल बनाकर; जन विश्वास अधिनियम के माध्यम से विभिन्न कानूनों के तहत 19 मंत्रालयों/विभागों के लगभग 183 प्रावधानों को अपराधमुक्त करके और निर्बाध और तेज मंजूरी देने के लिए राष्ट्रीय एकल विंडो प्रणाली (NSWS) की स्थापना करके एक अनुकूल और आकर्षक कारोबारी माहौल की शुरुआत की।

भाजपा ने भारत की विनिर्माण क्षमताओं में विश्वास किया और पिछली कांग्रेस/यूपीए सरकार की आयात पर निर्भरता की प्रवृत्ति को उलट दिया और विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां बनाईं।

सरकार ने 14 प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए एक 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ व्यापक उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना शुरू की।

बुनियादी ढांचे में रिकॉर्ड निवेश से वैश्विक प्रतिस्पर्धा के पैमाने को प्रोत्साहन और बढ़ावा मिल रहा है।

सरकार का फोकस सुरक्षित, विश्वसनीय और बेहतर गुणवत्ता वाले सामान उपलब्ध कराने और भारतीय उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत एवं गुणवत्तापूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करने पर है। मई, 2014 से पहले 106 उत्पादों को कवर करने वाले केवल 14 गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) जारी किए गए थे। सूची मे 653 उत्पादों को शामिल करते हुए अब इसे 148 क्यूसीओ तक बढ़ा दिया गया है।

वन-डिस्ट्रिक्ट-वन-प्रोडक्ट (One District One Product),

वोकल फॉर लोकल (Vocal for Local), लोकल फॉर ग्लोबल (Local for Global) जैसी पहलों से भारतीय कलाकारों, छोटे व्यवसायों और मेड इन इंडिया उत्पादों को बढ़ावा मिला है।

आज, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर सेमीकंडक्टर, विमानन और घटकों तक विनिर्माण क्षेत्र में निवेश और रोजगार सृजन अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है। वैश्विक विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में भारत की हिस्सेदारी बढ़ रही है और एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में इसकी उपस्थिति का विस्तार हो रहा है।

सरकार के प्रयासों की सफलता सभी क्षेत्रों में पहले से ही दिखाई दे रही है:

- 2014 में लगभग सभी स्मार्टफोन आयात करने की तुलना में आज भारत में स्मार्टफोन के घरेलू उत्पादन में 11 गुना वृद्धि देखी गई है और यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन का विनिर्माता बन गया है। चालू वित्त वर्ष में 1,00,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के स्मार्टफ़ोन का निर्यात किया जा चूका है।
- एप्पल, सैमसंग, मोटोरोला, गूगल जैसे वैश्विक स्मार्टफोन ब्रांडों सहित प्रत्येक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड भारत को अपना पसंदीदा विनिर्माण आधार बना रहा है।
- वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर के क्षेत्र की हर नामचीन कंपनी ने भारत में अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित किया है और कई भारत में सेमीकंडक्टर संयंत्रों की पैकेजिंग और निर्माण के लिए संयंत्र स्थापित कर रही हैं – इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सेमीकॉन इंडिया नीतियों को जाता है। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव, औद्योगिक, दूरसंचार और अन्य विनिर्माण क्षेत्रों को और बढ़ावा मिलेगा।
- जो भारत खिलौने आयात करता था, आज वह 'मेड इन इंडिया' खिलौने निर्यात कर रहा है। 2014-15 और 2022-23 के बीच खिलौनों के कुल आयात में 52% की कमी और खिलौनों के निर्यात में 239% की वृद्धि देखी है।
- भारत का फार्मा (Pharma) निर्यात दोगुना से अधिक हो गया है।

- भारत का रक्षा उत्पादन एक लाख करोड़ रुपये के ऐतिहासिक स्तर को पार कर गया है। भारत का रक्षा निर्यात भी अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जो 2013-14 में 686 करोड़ रुपये से 23 गुना बढ़कर 2022-23 में लगभग 16,000 करोड़ रुपये हो गया है।
- आज, हर भारतीय चंद्रयान 3, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला दुनिया का पहला लैंडर और देश के स्वदेशी विमान वाहक आईएनएस विक्रांत पर गर्व महसूस करता है - जो भारत की मेगा इंजीनियरी क्षमताओं के साथ-साथ माइक्रो-इलेक्ट्रॉनिक्स ताकत का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। सी-295 जैसे आधुनिक और बड़े परिवहन विमान का विनिर्माण हमारी आत्मनिर्भर रक्षा में एक और माइलस्टोन साबित होने वाला है।

कुल मिलाकर FDI प्रवाह 2004-14 के दौरान 304 अरब डॉलर से दोगुना होकर 2014-2023 (सितंबर तक) के दौरान 629 अरब डॉलर हो गया है। भारत में निवेश करने का इससे बेहतर समय कभी नहीं रहा! GIFT IFSC (अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र) और एकीकृत नियामक प्राधिकरण, IFSCA अर्थव्यवस्था के लिए वैश्विक पूंजी और वित्तीय सेवाओं के लिए एक सुदृढ़ प्रवेश द्वार बना रहे हैं। सरकार निरंतर विदेशी निवेश के लिए कई द्विपक्षीय निवेश संधियों पर भी बातचीत कर रही है।

कभी प्रौद्योगिकी का महज कंज्यूमर रहा भारत आज प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी उत्पादों, डिवाइसेस का प्रोड्यूसर भी है और दुनिया के लिए आईपी, प्लेटफार्म एवं प्रौद्योगिकी समाधान प्रदाता भी।

भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकास करने वाली डिजिटल और नवाचार अर्थव्यवस्था के रूप में उभरकर सामने आया है। डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकार, निवेश और नौकरियाँ पहले से कहीं अधिक तेज़ी से बढ़ रहे हैं। नवाचार और डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारत की उपस्थिति जो 2014 में काफी हद तक IT/ITeS तक सीमित थी, अब प्रौद्योगिकी और नवाचार के पूरे स्पेक्ट्रम में फैल गई है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि जैसी उभरती हुई प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। नवाचार और प्रौद्योगिकी में भारत की बढ़ती हुई ताकत तथा तकनीकी के

भविष्य को आकार देने में इसकी भूमिका अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान, फ्रांस जैसे दुनिया के अग्रणी देशों के साथ भारत की उभरती हुई वैश्विक तकनीकी साझेदारी से स्पष्ट है, जिसमें उभरती हुई महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र भी शामिल हैं।

भारत ने बौद्धिक संपदा अधिकार फाइलिंग (IPR filings) में कई अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ दिया है। वर्तमान में पेटेंट फाइलिंग के मामले में भारत दुनिया में छठे स्थान पर है, जो खुद को वैश्विक ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था में एक पावरहाउस के रूप में स्थापित कर रहा है। दायर और दिए गए पेटेंट की संख्या 2004-14 के दौरान महज क्रमशः 3.89 लाख और 71,558 थी जो बढ़कर 2014-24 के बीच 5.62 लाख और 2.46 लाख हो गई है।

जैसा कि नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर ए. माइकल स्पेंस ने हाल ही में कहा है, "भारत ने दुनिया में अब तक की सबसे अच्छी डिजिटल अर्थव्यवस्था और वित्तीय संरचना सफलतापूर्वक विकसित की है"।

वैश्विक आपूर्ति और नवाचार श्रृंखलाएं आज भारत को एक विश्वसनीय भागीदार और निवेश और प्रतिभा के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में देख रही हैं।

विशेष रूप से वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं और सामान्य तौर पर प्रौद्योगिकी एवं विनिर्माण में भारत की उपस्थिति का और अधिक विस्तार होने जा रहा है। प्रधानमंत्री के अथक प्रयासों और वैश्विक करिश्मे की बदौलत 'मेड इन इंडिया' और 'डिज़ाइन्ड इन इंडिया' वैश्विक ब्रांड बनने जा रहे हैं।

आज दुनिया मानती है कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला भारत के बिना अधूरी है और विश्व के लिए मेक इन इंडिया के लिए आत्मविश्वास से आगे बढ़ रही है।

VIII. युवा शक्ति – उद्यमिता और नवाचार

भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी बसती है और युवा शक्ति भारत के विकास यात्रा की प्रेरक शक्ति है। अगले 25 वर्ष राष्ट्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण हैं। युवा शक्ति के सपने भारत की दिशा तय करेंगे। युवा शक्ति की आकांक्षाएं ही भारत की मंजिल तय करेंगी। युवा शक्ति का जुनून

भारत का रास्ता तय करेगा।

आजादी के 67 वर्ष बाद UPA सरकार ने 2014 में देश को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया, जब अधिकांश युवाओं के पास शिक्षा और कौशल दोनों का अभाव था। कार्यबल में शामिल 42 करोड़ लोगों में करीब 30 करोड़ के पास न तो औपचारिक कौशल था और न ही शिक्षा। स्कूली शिक्षा छोड़कर लगभग 1.5 करोड़ युवा बिना किसी कौशल के हर साल कार्यबल का हिस्सा बन रहे थे। इस प्रकार, हमारे कार्यबल में देश के 4 में से 3 युवा जरूरी कौशल या शिक्षा के बिना अपना और अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए मजबूर थे।

भारत के 'अमृत काल' में कौशल और शिक्षा का सर्वाधिक महत्व होगा।

2014 के बाद भाजपा सरकार ने सिलसिलेवार तरीके से अनेक योजनाओं एवं पहलों की शुरुआत की जिनका मकसद युवाओं को उद्योग की जरूरतों के अनुरूप तैयार करना और उद्यमशीलता और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना था, ताकि युवा नौकरी मांगने वाला 'Job Seeker' नहीं बल्कि नौकरी पैदा करने वाला 'Job Creator' यानी रोजगारदाता बन सके। यह यूपीए युग से एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जहां युवाओं को उनके हाल पर छोड़ दिया गया था और केवल विशेषाधिकार प्राप्त कुछ ही लोगों की शिक्षा, कौशल और पूंजी तक पहुंच थी।

सरकार ने एक अनुकूल कौशल इकोसिस्टम बनाया है और 6 करोड़ से अधिक युवाओं को कुशल बनाया है। इसने प्रशिक्षण और कौशल केंद्रों का एक मजबूत नेटवर्क स्थापित किया है, जो वार्षिक आधार पर लगभग 20 लाख उम्मीदवारों को आसानी से कौशल प्रदान कर सकता है। हाल ही में लॉन्च किया गया स्किल इंडिया डिजिटल के तहत कौशल और आजीविका से संबंधित सभी प्रमुख हितधारकों और सेवाओं को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) और 'PM SHRI विद्यालयों' के माध्यम से भारत में शिक्षा और कौशल में बदलाव लाने की कोशिश की गई है। इस प्रकार, श्रम बल में शामिल होने वाले नये युवाओं में अकुशल लोगों की संख्या कम हो रही है। स्कूली छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार 14,000 से अधिक मौजूदा स्कूलों को 'PM SHRI विद्यालयों' के रूप में विकसित कर रही है, जिनमें से 6,000 से अधिक

स्कूल तैयार हो चुके हैं।

सरकार अटल टिंकरिंग लैब (Atal Tinkering Lab) के माध्यम से कम उम्र में ही बच्चों में रचनात्मकता और नवाचार के बीज बो रही है। लाखों बच्चों और युवाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन (Atal Innovation Mission) के तहत 10,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए गए हैं।

- सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आय सृजन गतिविधियों के लिए कोलेटेरल फ्री यानी किसी प्रकार की संपत्ति गिरवी रखने के बगैर 46 करोड़ से अधिक कर्ज को मंजूरी दी गई, जिनमें से 31 करोड़ से अधिक ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए हैं।
- लगभग 2.15 लाख महिलाओं/एससी/एसटी उद्यमियों को स्टैंड-अप इंडिया के तहत एक नया व्यवसाय शुरू करने के लिए लगभग 49,000 करोड़ रुपये के बैंक ऋण मंजूर किए गए हैं।
- पीएम स्वनिधि योजना के तहत 63.4 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को कॉलेटरल-फ्री ऋण के रूप में 10,000 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं, जिनमें से लगभग 2.6 लाख को तीसरी बार क्रेडिट मिला है।
- 18 ट्रेडों में 84 लाख से अधिक विश्वकर्मा यानी पारंपरिक कलाकारों और शिल्पकारों के परिवारों को कौशल प्रशिक्षण और कॉलेटरल-फ्री ऋण सहित एंड-टू-एंड समग्र सहायता प्रदान की जा रही है।
- लगभग 3.7 करोड़ एमएसएमई उद्यम और उद्यम असिस्ट पोर्टल पर पंजीकृत हैं। MSME के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत गारंटी के रूप में पिछले कुछ वर्षों में लगभग 5 लाख करोड़ रुपये (2014 से पहले की तुलना में 6 गुना अधिक) स्वीकृत किए गए हैं। लगभग 14 वर्षों के बाद MSME की परिभाषा को आखिरकार एमएसएमई के सुदृढ़ीकरण और विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिए विस्तारित किया गया है।
- स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम भारत में नवाचार के विचारों के लिए एक लॉन्चपैड बन गया है। विभिन्न नीतियों के अलावा, यह योजना हमारे युवाओं को रोजगारदाता के रूप में बदलने के लिए कर लाभ, फंड ऑफ फंड्स, सीड फंड स्कीम और स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी योजनाओं का

समर्थन करती है।

पिछले 10 वर्षों में भारत स्टार्टअप्स के लिए एक जीवंत वैश्विक केंद्र के रूप में उभरा है और अब दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। इसके पास 1.2 लाख पंजीकृत स्टार्टअप और 113 यूनिकॉर्न हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं, जो 12.42 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार तैयार करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि विश्व स्तर पर प्रत्येक 10 में से 1 यूनिकॉर्न भारत में तैयार हुआ है, और वे अब डेकाकॉर्न बनने के लिए परिवर्तित हो रहे हैं। टेक स्टार्टअप्स में 15 गुना भारी उछाल देखने के बाद भारत अब इनोवेशन की अगली लहर की तैयारी कर रहा है जो डीपटेक - आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), वेब 3, ब्लॉकचेन और बहुत कुछ में स्टार्टअप्स द्वारा संचालित होगा।

सरकार ने उद्यमशीलता और कौशल पारिस्थितिकी तंत्र के फलने-फूलने के लिए और हमारे युवाओं के दिमाग और भाग्य में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए एक मजबूत नींव रखी है। आजादी के बाद यह पहली बार है कि युवा भारतीयों को नौकरियों और उद्यमिता में इस तरह के अभूतपूर्व अवसर मिले हैं। यह बदलाव हर गांव, शहर और कस्बे में दिखाई दे रहा है। भारत का रैंक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इस सरकार द्वारा किए गए कार्यों का प्रमाण है – केवल 10 वर्षों में भारत 2015 में 81वें रैंक से 2023 में 40वें रैंक पर पहुंच गया है।

युवा शक्ति अब भविष्य को उद्देश्य और आशा की एक नई भावना के साथ देख रही है!

IX. विश्व के अग्रणी देश / विश्व–गुरु के रूप में भारत

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सबल और दूरदर्शी नेतृत्व में वैश्विक मंच पर भारत की रुतबा बढ़ा है। पहले की तरह अब यह महज मूकदर्शक नहीं रहा बल्कि वैश्विक एजेंडा तय करने, कूटनीतिक प्रतिबद्धताओं को बढ़ावा देने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। भारत आज दुनिया के लिए एक रणनीतिक साझीदार के तौर पर उभरा है। इस बदलाव का श्रेय प्रधानमंत्री जी को जाता है।

दुनिया के लिए बहुत कठिन समय के दौरान भारत ने ताकतवर देशों का

मंच G20, 2023 की अध्यक्षता संभाली। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक एवं निर्णायक क्षण था। G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत द्वारा निभाई गई भूमिका के कारण ही सर्वसम्मत नेताओं का घोषणा पत्र जारी हो सका। जो की इस बात का प्रमाण है कि भारत एक बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए सार्थक और अप्रत्याशित प्रयास करने में सक्षम है।

इस तरह भारत ने दुनिया के मंच पर 'विश्व मित्र' के रूप में अपनी जगह बनाई है। अफ्रीकी संघ को G20 के मंच पर एक स्थायी सदस्य के तौर पर लाकर भारत आज समकालीन दुनिया में 'वॉइस ऑफ़ द ग्लोबल साउथ' बन गया है। अफ्रीकी संघ को G20 टेबल पर एक स्थायी सीट सुरक्षित करने में मदद की और साथ ही अन्य प्लेटफार्मों पर भी ग्लोबल साउथ के मुद्दे का जोरदार समर्थन किया है।

भारत को अब स्थिरता और सुरक्षा से लेकर Tech, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तक विभिन्न वैश्विक पहलों में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में पहचाना जा रहा है। QUAD, I2U2 से लेकर IPEF और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस (Global Biofuel Alliance), ऑस्ट्रेलिया, यूएई और मॉरीशस के साथ आर्थिक समझौतों एवं EFTA, EU और UK व अन्य कई वार्ताओं (negotiations) के बाद भारत को वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण सहयोगी और रणनीतिक साझेदार के रूप में देखा जा रहा है।

भारत वैश्विक समुदाय के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है और भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा दुनिया के साथ भारत के संबंधों में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए तैयार है।

भारत mega-scalable सार्वजनिक प्लेटफार्मों में बढ़ती क्षमताओं के साथ प्रौद्योगिकी में अग्रणी देश के रूप में उभरा है। India-Stack में आधार (डिजिटल पहचान), UPI (डिजिटल भुगतान), डिजिलॉकर (पेपरलेस गवर्नेंस), UMANG (मोबाइल गवर्नेंस) जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) अब वैश्विक स्तर पर भी जा रहे हैं। भविष्य में हर किसी पर और हर जगह भारतीय नवाचारों के छाप देखने को मिलेंगे।

भारत सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में नवीकरणीय क्षमता वृद्धि

की सबसे तेज़ गति प्राप्त कर चुका है। COP26 में भारत ने अपनी 'पंचामृत घोषणा' में स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में अपने परिवर्तन के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से दर्शाया है। वास्तव में भारत एकमात्र प्रमुख देश है जो अपने CoP26 के लक्ष्यों को प्राप्त करने की राह पर है।

कोविड-19 महामारी के दौरान भारत के प्रो-एक्टिव रिस्पांस ने विश्वभर के लोगों पर गहरा प्रभाव डाला। कोविड-19 महामारी से निपटने में भारत की तत्परता और कार्य-प्रणाली से दुनिया आज प्रेरणा ले रही है। खासतौर से भारत ने जिस तरह सफलतापूर्वक निरंतर आर्थिक सुधार की प्रक्रिया अपनाई है, उसे वैश्विक मंच पर इसने अपनी गहरी छाप छोड़ी है। कोविड से निपटने में भारत ने न सिर्फ अपने लिए तैयारी की, बल्कि 'वसुधैव कुटुंबकम' के दर्शन पर अमल करते हुए दुनिया के देशों की भी मदद की।

2014 से पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि भारत दुनिया में सबसे तेज टीकाकरण अभियान (1 साल 6 महीने में 200 करोड़ doses दी गई), दुनिया में सबसे बड़ा डिजिटल टीकाकरण अभियान (Co-Win app के माध्यम से 111 करोड़ पंजीकरण), दुनिया में सबसे अधिक एक-दिवसीय टीकाकरण (17 सितंबर 2021 को 2.5 करोड़ doses), साथ ही दुनिया के सबसे बड़े खाद्य वितरण कार्यक्रम (80 करोड़ भारतीयों को मुफ्त राशन वितरित करना) का नेतृत्व सकता है।

पूरा विश्व आज तेजी से भारत को पहचान रहा है और वैश्विक मंच पर उसे ऊंचे पायदान पर बैठाया जा है। आज इस बात का गहरा अहसास है कि मौजूदा वैश्विक समस्याओं का संभावित समाधान खोजने के लिए भारत की भागीदारी हर विषय में आवश्यक है।

भारत आत्मविश्वास के साथ 'विश्व गुरु' बनने राह पर अग्रसर है।

X. 'नए भारत' से 'विकसित भारत' की यात्रा

भारत ने बीते दस वर्षों में के दौरान अत्यंत सकारात्मक बदलाव का दौर देखा है। अगले कुछ साल में भारत की आजादी के सौ साल पूरे होंगे। भारतीयों में सकारात्मकता और आत्मविश्वास है। देश के उज्ज्वल भविष्य की कल्पना करते हुए वे आशा और विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं।

प्रभावी निष्पादन और 'जन कल्याण' के साथ शासन-व्यवस्था Governance, विकास Development, और प्रदर्शन Performance (हमारी नई GDP) के अनुकरणीय ट्रैक रिकॉर्ड से सरकार को 'India – A Viksit Bharat' अर्थात 2047 तक एक अग्रणी और विकसित राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने के लिए लोगों का भरोसा, विश्वास और आशीर्वाद मिला है। यह इसलिए संभव हो पाया, क्योंकि भारत की जनता ने भाजपा को मजबूत जनादेश (Strong Mandate) दिया। मजबूत जनादेश (Strong Mandate) का मतलब मजबूत सरकार (Strong Government) और मजबूत सरकार (Strong Government) होने से देश की अर्थव्यवस्था में मजबूती (Strong Economy) और इस तरह शक्तिशाली भारत (Strong Bharat) का निर्माण।

अमृतकाल का सफर अभी आरंभ हुआ है और और हमारा लक्ष्य है 'विकसित भारत' अर्थात 2047 तक एक अग्रणी और विकसित राष्ट्र बनना। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार यानी मोदी 3.0 'विकसित भारत' की नींव को मजबूत करने में पूरी ताकत झोंकेगी।

'विकसित भारत' के सपने को साकार करने की ओर बढ़ते कदम

1. भारत की अर्थव्यवस्था 2027 तक US $5 ट्रिलियन की बनेगी और 2047 तक US $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ भारत 'विकसित राष्ट्र बनेगा।
2. बुनियादी सुविधाओं और कल्याणकारी लाभों की डिलीवरी में परिपूर्णता - हर परिवार को पीएम आवास का लाभ, हर घर जल, हर घर पाइप से रसोई गैस की उपलब्धता, करोड़ों के बिजली बिल की बचत के लिए सौर ऊर्जा।
3. नव-मध्यम वर्ग को 'मोदी कवच'।
4. जीवन की सुगमता (Ease of Living) से लेकर सबका जीवन गुणवत्तापूर्ण (Quality of Life for All) बनाने तक का प्रयास।
5. सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा अवसंरचना और ज्यादा किफायती व सुलभ चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करना।

6. विश्व स्तरीय संस्थान/विश्वविद्यालय (IIT, IIM, AIIMS)- सबके के लिए शिक्षा सुलभ और खर्च कम।
7. गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए किफायती व आरामदेह यात्रा की सुविधा - बुलेट ट्रेनों की शुरुआत और वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत ट्रेनों का विस्तार।
8. कृषि में बदलाव – एग्रीटेक (AgriTech) को बढ़ावा, ड्रोन का उपयोग बढ़ाना, नैनो यूरिया के उपयोग को बढ़ावा, खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता पर जोर, प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन और सुपरफूड के रूप में श्री अन्न (मिलेट्स) का संवर्धन।
9. नई बुलंदियों को छूता आत्मनिर्भर भारत- हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता; 'मेड इन इंडिया' सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में दुनिया में दबदबा।
10. डिजिटल इकॉनमी - डिजिटल इकॉनमी की दुनिया में रहेगा भारत का दबदबा।
11. स्टार्टअप्स की नई लहर - Tier 2 व Tier 3 शहरों में और उभरती प्रौद्योगिकियों में युवाओं के स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न की संख्या में इजाफा; पेटेंट फाइलिंग में जोरदार उछाल।
12. भारत बनेगा दुनिया में ग्लोबल स्किल कैपिटल यानी विश्व में कौशल का केंद्र।
13. 'प्रकृति' और 'प्रगति' के बीच संतुलन - ऊर्जा यानी कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करते हुए ग्रीन हाइड्रोजन क्षमता का विस्तार, सार्वजनिक परिवहन को सस्ता बनाना।
14. भविष्य है इलेक्ट्रिक - ई-बसों को अपनाकर सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बदलना, इलेक्ट्रिक वाहन की बिक्री को बढ़ावा देना और चार्जिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करना।
15. नए सूचना प्रौद्योगिकी कानून (डिजिटल इंडिया एक्ट) के माध्यम से डिजिटल नागरिकों के लिए इंटरनेट को खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह बनाना।
16. सशक्त प्रदेश से सशक्त देशः देश के विकास के लिए राज्यों के

विकास के मंत्र को मजबूत प्रबल बनाना। सरकार निरंतर सहकारी प्रतिस्पर्धी संघवाद (cooperative competitive federalism) को प्रोत्साहन ।

सरकार 'विकसित भारत' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी स्तरों पर सुशासन की क्षमताओं को मजबूत करेगी, जवाबदेही सुनिश्चित करेगी, लोगों की ताकत बढ़ाएगी और उन्हें अपनी नियति को आकार देने के लिए सशक्त बनाएगी। विकास प्रक्रिया में हर भारतवासी - गरीब (गरीब), युवा (युवा), अन्नदाता (किसान), नारी शक्ति (महिला) के सक्रिय समावेशन, शक्ति, प्रतिबद्धता और कड़ी मेहनत से विकसित भारत की परिकल्पना और संकल्प को साकार करने में मदद करेगी।

हमारा 2047 के अमृत काल का संकल्प है भारत के स्वर्णिम काल को वापस हासिल करना। हमारे तीसरे कार्यकाल की नीतियां भारत को 'विकसित भारत' के इस लक्ष्य तक ले जाएंगी और हमारी भावी पीढ़ियों को विरासत में एक समृद्ध, मजबूत और सुरक्षित भारत मिलेगा।

भारत का भविष्य 'विकसित भारत' है!

श्रीमती निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मंत्री

यूपीए के तहत 2004-14 के बीच औसत वार्षिक मुद्रास्फीति 8.2% थी। यूपीए युग के अंतिम तीन वर्षों (2011-14) में औसत खुदरा मुद्रास्फीति बढ़ी और 9.8% तक पहुंच गई। उस समय औसत वैश्विक मुद्रास्फीति केवल 4-5% थी, लेकिन भारत में यह 9.8% थी।

यूपीए के तहत, 2012-14 के बीच 22 महीनों के लिए खुदरा मुद्रास्फीति 9% से अधिक थी।

हमारी सरकार के पिछले नौ वर्षों में खुदरा मुद्रास्फीति ज्यादातर 5% के आसपास रही है और कभी भी 8% से अधिक नहीं हुई है। वो लोग, जिनके राज में महंगाई दहाई के आंकड़े को पार कर गई, वो हमसे महंगाई पर सवाल पूछ रहे हैं।

09 फरवरी, 2024

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

हम एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उसे हासिल करते हैं और फिर उसे पूरा कर, उससे भी बड़ा लक्ष्य निर्धारित करते हैं। हमने गांवों और शहरों में गरीबों के लिए 4 करोड़ से ज्यादा घर बनाए हैं। अब हमने 2 करोड़ और नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है। हमारा प्रारंभिक लक्ष्य 2 करोड़ महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाना था। अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ 'लखपति दीदी' बनाने का कर दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना से गरीबों को बहुत मदद मिली है। अब इस योजना का लाभ आंगनबाडी और आशा कार्यकर्ताओं को भी मिलेगा।

01 फरवरी, 2024

भाजपा प्रकाशन विभाग
6-ए, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002